सरकार बंद करेगी चीनी निर्यात सब्सिडी!

मॉनसून की प्रगति पर बनी हुई है अनिश्चितता, कम बारिश होने पर सरकार नहीं चाहेगी निर्यात जारी रखना

रॉयटर्स
लंदन/नई दिल्ली, 11 जुलाई

मॉनसून आने में देरी के बाद इसकी प्रगति पर अनिश्चितता देश की चीनी नीति को जटिल बना रही है। इस बात के आसार बढ़ रहे हैं कि सरकार चीनी निर्यात सब्सिडी रोक सकती है, जिससे वैश्विक कीमतों में तेजी आ सकती है। सरकार की यह कोशिश होगी कि कच्ची चीनी के निर्यात पर वर्तमान प्रोत्साहनों को आगे बढ़ाने से पहले मॉनसून की बारिश का असर देखा जाए।

प्रोत्साहनों को वापस लेने से अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि भारत से निर्यात घटेगा। लंदन स्थित ब्रोकर मरेक्स स्पेक्ट्रोन के चीनी विश्लेषक रॉबिन शॉ ने कहा, 'अगर मॉनसून खराब रहा तो सरकार निर्यात नहीं करना चाहेगी और चीनी देश में ही रखना चाहेगी।' उन्होंने कहा, 'अगर मॉनसून ठीक रहा तो सरकार निर्यात रोकने की जरूरत महसूस नहीं करेगी।' हालांकि विश्लेषकों और डीलरों ने कहा कि देश में गन्ने का ज्यादातर उत्पादन सिंचाई से होता है और अगर मॉनसून सामान्य से कम भी रहा तो जलाशयों में पर्याप्त पानी है। पिछले महीने की शुरुआत से देश में कमजोर मॉनसून से पिछले पांच वर्षों में पहली बार सूखे की आशंका पैदा

हो गई है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों को उम्मीद है कि अगले सप्ताह से बारिश रफ्तार पकड़ेगी। बॉम्बे शुगर मर्चेन्ट एसोसिएशन के महासचिव मुकेश कुवदिया ने कहा, 'मेरा मानना है कि सरकार निर्यात के लिए कच्ची चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने से पहले मॉनसून और गन्ने पर इसके असर को देखेगी।' उन्होंने कहा, 'पहले निर्यात को प्रोत्साहन देना और फिर आयात करना तर्कसंगत नहीं है।' इस समय देश में चीनी की कीमतें वैश्विक कीमतों की तुलना में कम हैं, जिससे आयात करना फायदेमंद नहीं है। कच्ची चीनी का निर्यात नहीं हो रहा है, क्योंकि मिलें पहले ही कच्ची चीनी के अपने ज्यादातर स्टॉक की बिक्री कर चुकी हैं।

शुल्क बढ़ाने की हाल की घोषणा पर कुवदिया ने कहा, 'आयात और निर्यात के मोर्चे पर

सरकार निर्यात के लिए कच्ची चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने से पहले मॉनसून और गन्ने पर इसके असर को देखेगी

यथास्थिति बनी हुई है, इसलिए सरकार के आयात शुल्क वर्तमान 15 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के आधिकारिक आदेश का कोई बड़ा असर नहीं होगा।' उन्होंने कहा, 'सब कुछ इस साल मॉनसून की बारिश पर टिका है।' चीनी पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने से पहले इस महीने ब्राजील से कच्ची चीनी का बड़ी मात्रा में आयात हो रहा है।

दिल्ली की एक फर्म शुगरेन ट्रेडिंग एलपी में साझेदार धर्मेन्द्र भयाना ने कहा कि कमजोर मॉनसून से अगले सीजन के शुरुआत में बड़े पैमाने पर निर्यात से उसके बाद के वर्ष में किल्लत पैदा हो सकती है।

अगले सीजन में बढ़ेगा चीनी उत्पादन

मॉनसून की अनिश्चितताओं और बारिश की कमी से गन्ने का रकबा घटा है, लेकिन पेराई सीजन 2014-15 में चीनी का उत्पादन 4 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। इस उद्योग की शीर्ष संस्था इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल अक्टूबर से शुरू हो रहे आगामी पेराई सीजन में चीनी उत्पादन 253 लाख टन रहेगा। पिछले पेराई सीजन में देश का कुल चीनी उत्पादन 243 लाख टन रहा था। हालांकि ज्यादा उत्पादन मिलों की अतिरिक्त चीनी स्टॉक की वर्तमान चिंता को और बढ़ाएगा। जब तक चीनी मिलों की आमदनी में सुधार नहीं होगा और लागत नहीं घटेगी, तब तक उनकी वित्तीय स्थिति नहीं सुधरेगी। ऐसी स्थिति में इस बार की तरह गन्ने के बकाये में बढ़ोतरी होगी।

इस्मा ने एक बयान में कहा, 'रकबे, अनुमानित उत्पादन, चीनी रिकवरी, चीनी उद्योग की गन्ने की खरीद, बारिश की वर्तमान प्रगति और जलाशयों में पानी की उपलब्धता के आधार पर आगामी पेराई सीजन 2014-15 में चीनी उत्पादन करीब 253 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि चालू सीजन में उत्पादन करीब 243 लाख टन रहा है।' जून के मध्य में ली गई उपग्रह तस्वीरों से पता चलता है कि पेराई सीजन 2014-15 में रकबा 52.3 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल से 2 फीसदी कम है। हालांकि कुल रकबे में कमी के आनुपातिक नुकसान की भरपाई होगी बल्कि उत्पादन बढ़ेगा। इसकी वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे ज्यादा रिकवरी वाले राज्यों में रकबा बढ़ना है। इन राज्यों में औसत रिकवरी 11.5 फीसदी से ज्यादा होती है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में रिकवरी 9.5 फीसदी के आसपास होती है। इस्मा के अनुमान में कहा गया है कि जहां महाराष्ट्र और कर्नाटक में रकबा बढ़ा है, वहीं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में यह घटा है। महाराष्ट्र में 18 और 15 महीने की फसल का हिस्सा बढ़ने से गन्ने का रकबा 13 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में इस साल रकबा 9 फीसदी कम रहने की संभावना है। हालांकि कृषि मंत्रालय ने इस साल 34.5 करोड़ टन गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। *बीएस*

Business Standard
12/7/14